SKC-SCH/3J/6.00

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In any case, you have got only one more minute.

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU: Sir, I am about to conclude my speech.

I empathize and sympathize with my brothers and sisters from Gujarat for incurring huge losses worth Rs. 20,000 crore due to the hasty exploration efforts made through State Government-owned corporations. If adequate support in the field of engineering, technology and exploration had been provided through such institutes, they would not have incurred such losses. Please empower the institutes to serve the national needs. Thank you.

(Ends)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you, Mr. Rapolu. You adhered to the six minutes-time. Now, the hon. Minister to reply.

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री धर्मेंद्र प्रधान) : उपसभापति जी, बहुत सारे माननीय सदस्यों ने कई महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर इस बिल के बारे में अपने सुझाव दिए, इसके लिए सबसे पहले मैं सदन के उन सदस्यों का आभारी हूं। इस बिल के बारे में चर्चा करते हुए सभी ने इसे एक सर्वसम्मत समर्थन दिया। जैसा कि बताया गया कि आन्ध्र प्रदेश के विभाजन के समय कई विषयों को पारित करते हुए और बिल के कंपोनेंट

बनाते हुए, एक प्रतिबद्धता यह भी थी कि Indian Institute of Petroleum and Energy के प्रतिष्ठान की स्थापना आन्ध्र प्रदेश में की जाएगी। उसी प्रतिबद्धता के आधार पर इस साल सरकार ने इसका निर्णय लिया है। पिछले academic session से Visakhapatnam University Campus में इस इंस्टीट्यूट की पढ़ाई भी शुरू हो चुकी है। IIT, Kharagpur को उसका mentor organization बनाया गया है। अभी हम इसके दूसरे शिक्षा वर्ष में चल रहे हैं।

आन्ध्र प्रदेश सरकार ने इसके लिए 200 एकड़ जमीन दी, जिसके लिए मैं आन्ध्र प्रदेश की सरकार का बहुत आभारी हूं। उन्होंने वादे के मुताबिक free of cost land उपलब्ध करवाई है। भारत सरकार के माध्यम से इसका जो प्रोजेक्ट बनाया गया है, उसके अनुसार इस इंस्टीट्यूट के बनने में लगभग 1055 करोड़ की लागत आएगी। भारत सरकार budget allocation के माध्यम से 655 करोड़ 46 लाख रुपये का वित्तीय प्रबंधन करेगी और 400 करोड़ रुपया अलग-अलग oil companies के द्वारा एक endowment के माध्यम से दिया जाएगा, ताकि उसका recurring खर्च चल सके। 655 करोड़ रुपये उस इंस्टीट्यूट को प्रारम्भिक अवस्था में build-up करने के लिए खर्च किए जाएंगे और 400 करोड़ रुपये endowment के द्वारा एफडी के रूप में रखे जाएंगे, जिससे उस इंस्टीट्यूट के recurring खर्च का भुगतान शुरू हो सकेगा। आन्ध्र प्रदेश सरकार और केन्द्र सरकार की यह अपेक्षा है और यह संभावना है, वह institute थोड़े ही दिनों में अपने आप स्वतंत्र हो सकेगा। जैसे भारत के अन्य IITs/IIMs की government allocation के बाद भी अपनी financial autonomy होती है, हमारी

अपेक्षा है कि यह इंस्टीट्यूट भी उसी दिशा में आगे बढ़ेगा, सरकार ने भी उसी दिशा में इसका प्रबंधन करना शुरू कर दिया है।

अगर मैं इसको sum-up करूं, तो संक्षेप में मैं दो-तीन विषय कहूंगा। सबने एक बहुत ही वाजिब चिंता जाहिर की है कि इसकी autonomy के बारे में क्या होगा? यह बात अलग है कि आज तक जो लोग सरकार में रहे, वे अपने तरीके से व्यवस्थाओं को चलाते रहे, लेकिन उनके सुझाव महत्वपूर्ण हैं और मैं उनके सुझावों को आदर से स्वीकार करता हूं। इसकी autonomy को समाप्त करने की हमारी कोई मंशा नहीं है। आगे चल कर यह इंस्टीट्यूट स्वतंत्र हो, इस सरकार की यही इच्छा और मंशा है। इस सदन के अंदर आज की चर्चा को साक्षी रखते हुए मैं आप सभी को इसके लिए आश्वस्त करना चाहूंगा कि यह autonomous ही रहेगा।

इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण लोगों को रखा गया है। Indian Institute of Science, Indian Institute of Chemical Technology, Hyderabad के प्रतिनिधि में इसमें रहेंगे, नीति आयोग के प्रतिनिधि भी इसमें रहेंगे और उसके साथ-साथ पांच विशेषज्ञ भी इसमें रहेंगे। दुनिया के एनर्जी सेक्टर के जो जानकार लोग हैं, वे इसमें सदस्य रहेंगे।

(3k/rpm पर जारी)

RPM-HK/3K/6.05

श्री धर्मेंद्र प्रधान (क्रमागत) : ऑयल मार्केटिंग के, ऑयल कंपनियों के अधिकारी भी उसमें रहेंगे। इसे गिनते हैं, तो भारत सरकार का पक्ष ज्यादा हैवी दिखता है, लेकिन क्या हम इसे डे वन से बीएचयू मानेंगे, क्या हम इसे डे वन से जेएनयू मान सकते हैं,

क्या डीयू मान सकते हैं, क्या चेन्नई यूनिवर्सिटी मान सकते हैं, शायद नहीं। प्रारंभिक अवस्था में इसकी हैंड -होल्डिंग की आवश्यकता होगी। उसके वित्तीय प्रबन्धन के लिए इन सारे कॉरपोरेट को इकट्ठा किया गया है। उसकी एकेडेमिक ऑटोनॉमी के लिए अथॉरिटी स्वतंत्र है। इसमें किस प्रकार के कोर्स चलाए जाएंगे और इसमें किस प्रकार से नियुक्तियां की जाएंगी, इसके बारे में यह संस्था स्वतंत्र रूप से काम करेगी।

महोदय, यह बात सही है कि भारत के संविधान के तहत जो आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं, उनके अनुसार शिक्षा और गैर-शिक्षा के क्षेत्र में जितनी भी नियुक्तियां होंगी, उनका पालन पूर्ण रूप से किया जाएगा। इस बात का इस बिल में प्रोविज़न रखा गया है।

महोदय, मैं एक और विषय पर बहुत प्रसन्न हूं और इसके लिए मैं सदन का आभारी हूं कि सभी ने इस विषय पर चिन्ता जाहिर की है। इस देश की जो ऊर्जा आवश्यकता है, उसे पूरा करने के लिए यह बात सही है कि आजादी के 70 साल के बाद भी आज हम एनर्जी सिक्योरिटी की ओर, फिर चाहे ट्रांसपोर्टेशन में हो, हाइड्रोकार्बन में हो, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में हो या रिन्यूअल एनर्जी के क्षेत्र में हो, हम इंडिपेंडेंट नहीं हो पाए हैं। इस सरकार के आने से चार या पांच साल पहले जो सोलर एनर्जी की प्रति यूनिट कॉस्ट 12 से 14 रुपए थी, वह इस सरकार के आने के बाद और इस सरकार द्वारा इस क्षेत्र में प्रयास करने के कारण अब ढाई या तीन रुपए प्रति यूनिट पर आ गई है।

माननीय उपसभापति जी, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि एनर्जी के क्षेत्र के विश्व के विशेषज्ञों का कहना है कि दुनिया में यदि एनर्जी के क्षेत्र में सबसे ज्यादा कहीं

काम हो रहा है या आने वाले 25 साल में काम होने वाला है, तो वह भारत है। वर्ष 2040 तक, यानी आने वाले 25 सालों में भारत की एनर्जी की जो खपत होगी, वह दुनिया की एनर्जी की खपत की लगभग 25 प्रतिशत होगी। Incremental requirement of energy, जितनी होगी, उसके 25 प्रतिशत भाग की खपत भारत में होगी। आज भारत विश्व का तीसरे नंबर का ऊर्जा खपतकारी देश है।

महोदय, यह बात सही है कि आज भी hydrocarbon के क्षेत्र में हमें अपनी आवश्यकता का 80 प्रतिशत बाहर से आयात करना पड़ रहा है। हम उसकी सीमा को जानते हैं। अगर हमारी Import dependency बढ़ेगी, तो हमारे ऊपर foreign exchange का बोझ भी बढ़ेगा और उससे हमारा एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा और जिस प्रकार से विश्व की geo-polity होती है, उसके हिसाब से हमारे देश को भी उसका शिकार बनना पड़ सकता है। ऊर्जा international commodity होने के कारण अमेरिका में कुछ रिफाइनरीज बन्द हो गईं। खाड़ी के दो देशों में कुछ राजनीतिक तनाव के कारण भी इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। इस चिन्ता को दूर करने के लिए, यह अपेक्षा करना गलत नहीं है, यदि मैं यह कहूं कि हमारे देश की शिक्षा नीति प्राइमरी स्कूलों पर रोक लगाने से नहीं बदलेगी। निश्चित रूप से यह इंस्टीट्यूट, उस टेक्नोलॉजी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए जहां सरकार ने Bifurcation Act में, इसके बारे में सोचा है वह सही सोचा गया है।

महोदय, आंध्र प्रदेश में इस प्रकार के एक इंस्टीट्यूट की आवश्यकता थी। मैं अपने मित्र, श्री रवि वर्मा जी का आभारी हूं। उन्होंने एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में

उल्लेख किया। मैं अपने वरिष्ठ सदस्य, श्री सी.पी. नारायणन जी का भी आभारी हूं। उन्होंने इसका जो scientific आस्पेक्ट है, उसकी ओर ध्यान दिलाया। KG Basin दुनिया का सबसे prolific basin बनता जा रहा है। आने वाले 10 सालों में 60-70 हजार करोड़ रुपए का खर्च exploration activities, refinery activities और petro-chemical activities पर आंध्र प्रदेश में होने वाला है।

महोदय, gas hydrates के इतने ज्यादा भंडार केजी बेसिन में हैं, लेकिन आज सबसे बड़ी चुनौती है कि उस गहरे पानी से हाइड्रोकार्बन को, उस रिसोर्स को हम कैसे मॉनिटाइज करें, बाजार तक लाएं और रिफाइनरी तक लाएं। इस प्रकार का इंस्टीट्यूट आज विश्व भर में अमेरिका के Shale Revolution को इन दिनों में, पिछले दो-तीन दशकों के अंदर एनर्जी सेक्टर की एक बड़ी उपलब्धि माना जाता है। यदि उसका श्रेय किसी को जाता है, तो वह Texas University और Houston University को जाता है। आज हमारे देश में अनेक इंस्टीट्यूट हैं। सारे आईआईटी उस दिशा में काम कर रहे हैं। हमारे दो-तीन स्पेशियलाइज्ड इंस्टीट्यूट्स भी इस दिशा में काम कर रहे हैं। मैं यदि स्पष्ट रूप से कहूं और यह कहूं कि देहरादून के बारे में बार-बार कहा गया, तो मैं कहना चाहता हूं कि वह CSR Laboratory है, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, लेकिन वह भी काम कर रहा है। मैं मानता हूं कि field and laboratory पहली बार, एक बढ़िया जोड़ी के रूप में काम कर रही है और यह शायद IIPE के अंदर होगी। बाकी कई सदस्यों ने छोटे-छोटे सुझाव भी दिए हैं।

(3 एल/पीएसवी पर जारी)

KSK/PSV/6.10/3L

श्री धर्मेंद्र प्रधान (क्रमागत): कई सदस्यों ने अपनी बात कहते हुए छोटे-छोटे सुझाव भी दिये हैं। जैसे मेरे मित्र रिपुन बोरा जी ने असम के बारे में कहा कि असम की ऑटोनॉमी के बारे में क्या सोच रहे हैं? मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण विषय उठाया। RGIPT के अन्तर्गत-- मैं अब कहूँगा तो शायद रिपुन बोरा जी थोड़ा नाराज भी हो सकते हैं। प्रधान मंत्री जी की घोषणा, कैसे काम नहीं किया जाता है, उसका बेस्ट एग्जाम्पल, रिपुन जी अगर आयेंगे तो मैं फाइल भी खोल कर दिखा दूँगा। रिपुन जी, सिर्फ घोषणा ही काम नहीं होता है, काम करना पड़ता है। मैं आपको सूचनार्थ बताऊँ कि हम लोगों ने इसी साल से इंस्टीट्यूट शुरू कर दिया है। घोषणा 8-9 साल पहले की गई थी। आपने कई बार उस पर भाषण भी दिया होगा, लेकिन हमने पिछले एकेडेमिक सेशन से उसमें पढ़ाई शुरू करा दी है। हम चाहते हैं, यह सरकार चाहती है कि वह इस प्रकार की, विशाखापट्नम जैसी एक ऑटोनॉमस और इंडिपेंडेंट बॉडी बने। हम शीघ्र ही उसके लिए भी सुधार/संशोधन आपके पास लेकर आयेंगे और आपके समर्थन की अपेक्षा करेंगे।

SHRI RIPUN BORA: Sir, this is a matter of record. ...(Interruptions)...

श्री धर्मेंद्र प्रधान: मैं पहले कह दूँ, पूरा कर दूँ?

SHRI RIPUN BORA: It started functioning during the time of Congress Party. I welcome and appreciate that you are going to make this institution an institution of national importance.

श्री धर्मेंद्र प्रधानः उपसभापति जी, मैं रिकॉर्ड स्ट्रेट कर दूँ। मैं सदन में जिम्मेवारी के साथ कहता हूँ। मैं सार्वजनिक भी कह सकता हूँ, नहीं तो रिपुन जी आयें, तो मैं उनको कागज दिखा दूँ। वह सिर्फ घोषणा ही थी। असम सरकार ने एक जमीन दी थी।

श्री भुवनेश्वर कालिताः लैंड एलोकेशन भी हुआ था।

श्री धर्मेंद्र प्रधानः दादा, मैं यहाँ कैसे असत्य कह सकता हूँ! जमीन ही एलोकेट हुई थी, बस! माँ कामाख्या देवी की जय, इतना ही हुआ था। हमने उसको खोला, एडमिशन करवाया, इस बार पैसे का भी प्रबंधन किया है और इसके लिए हम बिल भी लेकर आयेंगे।

SHRI BHUBANESWAR KALITA: It was started in a temporary campus.

श्री धर्मेंद्र प्रधानः मैं yield नहीं कर रहा हूँ। हम बिल लेकर आयेंगे। रिपुन जी की अपेक्षा से उसको ऑटोनॉमस करके चलायेंगे। हम पीछे हटने वालों में नहीं हैं, जिम्मेवारी लेने वालों में हैं। इस पर कई लोगों के सुझाव आये हैं। अन्य कई सुझाव आये हैं और बिल से बाहर के भी सुझाव आये हैं। मैं सबका आभारी हूँ। देश में लोक सभा द्वारा पारित किया हुआ, आज राज्य सभा द्वारा पारित करने के बाद, जो एक एकेडेमिक इंस्टीट्यूट दो साल से चल पड़ा है, उसको आज एक संवैधानिक/कानूनी मान्यता मिलेगी। इसके लिए मैं सदन का आभारी हूँ। इस महत्वपूर्ण बिल को सर्वसम्मति से समर्थन करने के लिए धन्यवाद।

(समाप्त)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, the question is:

That the Bill to declare the institution known as the Indian Institute of Petroleum and Energy to be an institution of national importance and to provide for its incorporation and for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 4 were added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 5, there is one Amendment (No.1) by Dr. T. Subbarami Reddy. He is absent. So, the Amendment is not moved.

Clause 5 was added to the Bill.

SHRI T.K. RANGARAJAN: Sir, we are saying, 'ayes', but they are keeping quiet. The Treasury Benches are keeping quiet. ...(Interruptions)... Suppose I say, 'noes', then they will shout. But when I say 'ayes', they keep quiet.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That's good. They welcome your saying, 'ayes'.

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI RAVI SHANKAR PRASAD): Sir, we don't have the sterling eloquence of Rangarajanji. ...(Interruptions)...

Clauses 6 to 8 were added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 9, there are five Amendments (Nos. 2 to 6) by Dr. T. Subbarami Reddy. He is absent. So, the Amendments are not moved.

Clause 9 was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 10, there are three Amendments (Nos. 7 to 9) by Dr. T. Subbarami Reddy. He is absent. So, the Amendments are not moved.

Clause 10 was added to the Bill.

Clauses 11 to 14 were added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 15, there are two Amendments (Nos.10 and 11) by Dr. T. Subbarami Reddy. He is absent. So, the Amendments are not moved.

Clause 15 was added to the Bill.

Clauses 16 to 32 were added to the Bill.

(Followed by 3M – GSP)

GSP-VNK/3M/6.15

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 33, there is one Amendment (No. 12) by Dr. T. Subbarami Reddy. He is absent. So, the amendment is not moved.

Clause 33 was added to the Bill.

Clauses 34 to 45 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री धर्मेंद्र प्रधान : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

कि विधेयक को पारित किया जाए।

The question was put and the motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Bill is passed.

(Ends)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I thank every Member who cooperated in passing the two Bills and adhering to time.

SHRI T.K. RANGARAJAN: Sir, we are always cooperating.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, yes. Thank you. ...(Interruptions)... Now, let us take up Special Mentions. Members who want to read their Special Mention can do so.

(THE VICE-CHAIRMAN, SHRI TIRUCHI SIVA, in the Chair)

SPECIAL MENTIONS

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Shri Santiuse Kujur; not present. Shrimati Sasikala Pushpa.

DEMAND FOR TAKING STEPS TO RESCUE MISSING TAMIL NADU FISHERMEN AND PROVIDING RELIEF AND REHABILITATION TO FISHERMEN AFFECTED BY OCKHI CYCLONE

SHRIMATI SASIKALA PUSHPA (TAMIL NADU): Sir, a devastating 'Ockhi Cyclone' had hit the southern coastal areas of Tamil Nadu. There were intermittent rains in Kanyakumari District since 29th November, 2017, which turned into 'Ockhi Cyclone' and caused severe loss in the southern coastal areas in the State of Tamil Nadu particularly in Kanyakumari District. No proper warning was given by the Indian Meteorological Department about the Cyclone. The damage to life and property due to this cyclone was enormous. The power infrastructure, agriculture including horticulture and plantation crops, road networks, fisheries infrastructure and drinking water supply were severely affected and the normal life of the people had gone haywire.

The most affected in this disaster were fishermen. Fishermen, who

ventured into sea for fishing, were lost in high sea due to cyclone. The family of the lost fishermen are running from pillar to post to know the whereabouts of their beloved ones but they are not getting proper replies from the concerned authorities. Only one Coast Guard Aircraft Dornic 760 was pressed into services for aerial surveillance, which was not adequate and sufficient. The fate of around 2,500 fishermen who ventured into sea for deep sea fishing before 29th November, 2017 is still unknown. The family members of the affected fishermen who went to deep sea for fishing are registering their protest in one way or other, but no substantial relief has been given to them.

Sir, I urge the Government to take necessary steps to rescue the missing fishermen and provide relief and rehabilitation to the affected fishermen. Thank you. (Ends)

NEED FOR PROTECTING RIGHTS OF CANDIDATES FROM TAMIL NADU IN BANKING SERVICE RECRUITMENT EXAMINATION

DR. V. MAITREYAN (TAMIL NADU): Sir, the Institute of Banking Personnel Selection (IBPS) recruits candidates for various posts in banking sector throughout the country. The number of posts available is generally higher in

Tamil Nadu. However, relaxation of IBPS rules adversely affect candidates from Tamil Nadu. For a long time, knowledge of regional language of the State was compulsory for selection and posting to that state. Only candidates who studied Tamil were eligible for competing for clerical cadre posts in Tamil Nadu. But recently, this stipulation has been diluted and candidates from other States without the knowledge of Tamil are allowed to compete for the posts in Tamil Nadu. They are given enough time to clear a basic test in Tamil and thus they are absorbed by the banks in Tamil Nadu. Candidates who qualify such tests do not have the required day-to-day knowledge in spoken or written Tamil. Bank customers in the rural areas face a lot of hardship in communicating with them. At a time when the hon'ble Prime Minister has been striving hard to get all the citizens into the banking system, unfortunately, bank recruiters are estranging people from banking system by posting non-Tamils in the banks situated in Tamil Nadu.

The decision to dilute knowledge of regional language has also jeopardized the career of over ten lakh educated youth in Tamil Nadu as the posts are usurped by candidates from other States. Therefore, I appeal to the Government to make the knowledge of regional language compulsory

for banking posts and save the livelihood of unemployed youth of Tamil Nadu. (Ends) (Followed by SK/3N)

SK/3N/6.20

DEMAND FOR ADDRESSING PROBLEM OF BITCOINS NETWORK IN COUNTRY

SHRI AMAR SHANKAR SABLE (MAHARASHTRA): Sir, through you, I wish to draw the attention of the Government towards the negative implications of Bitcoin, a digital currency that has created havoc and panic in India in recent times.

A huge Bitcoin network is operating in the world. Innocent people are being attracted to participate in this network without any knowledge about its risk factors. Some Indian techies living abroad are trading in the digital currency, buying Bitcoins in overseas exchanges and selling them locally at higher prices. The Bitcoin-rupee swap rate went into a free fall after regulators in China forced BTC China, one of the world's biggest exchanges for the digital currency, to close down in September, 2017.

Sir, the money used to buy Bitcoin is completely untraceable and may be used for trading and other financial activities directly without any

accountability. I believe that money being used in the network is nothing but black money. I would like to know what efforts have been made by the Government, the RBI and the SEBI to regulate the use of virtual currencies such as Bitcoin. Through media reports, we come to know that RBI has not given any licence and authorization to deal with Bitcoin or any virtual currency, but then how illegal trading is taking place by using Bitcoin and people are being duped.

I urge upon the Government to go to the root of the problem and stop the Bitcoins network in India. Thank you. (Ends)

MR. VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Mr. Derek O'Brien, not present. Dr. Kanwar Deep Singh, not present. Prof. Rajeev Gowda, not present.

The House stands adjourned till 11.00 hours on Thursday, the 28th December, 2017.

The House then adjourned at twenty-three minutes past six of the clock till eleven of the clock on Thursday, the 28th December, 2017.